forthwith the expulsions of its members done without complying to the provisions of its own articles of association; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (f) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Income-tax assessment of Promoters of Hotel at Kanpur

4553. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether the Income-tax Department, Kanpur has determined the total amount of investment made in the construction of hotel building in M.G. Park, Cantonment, Kanpur;

(b) whether it is a fact that the assessees have been evading taxes without any legal check;

(c) what are the details of assessment made in respect of the assessees during the past 5 years;

(d) what are the sources of investment determined under the Income-tax Act for the building; and

(e) what steps are being taken to enforce the law against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir. As the hotel building, 'Upwan', being constructed by M/s Pandit Restaurant, 49/7, General Ganj, Kanpur, at M.G. Park, Cantonment, Kanpur, is still not complete, the amount of investment in the building has not been determined so far.

(b) There is no information with the Department that the assessees have been evading taxes.

(c) The details of the assessments made during the past 5 years are given in the statement annexed. (*See* below)

(d) The investment is from business accounts and is reflected in the balance-sheet of the assessee.

(e) If any infringement of the provisions of the Income-tax Act is noticed, appropriate action will be taken.

Statement

Sl. No.	Assessment Year	Section	Income Returned	Income Assessed
1.	1987-88	143(1)	62,060	62,060
2.	1988-89	143(1)	49,940	49,940
3.	1989-90	143(1)	64,950	64,950
4.	1990-91	143(1)	74,220	74,220
5.	1991-92	143(3)	70,310	70,310

Increase in Staff Strength of United Bank of India's Rural Branch

4554. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a rural branch of United Bank of India in the close vicinity of Falta Export Processing Zone is unable to serve the constituents for want of required number of staff;

(b) whether it is also a fact that the branch has raised deposits of more than Rs. 8 crores;

(c) whether any representations have been received by Government for increasing the number of staff in the branch for better service; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) Information is being collected, and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

फसल के नष्ट होने की समस्या का सामना कर रहे किसानों के लिए ऋण माफी योजना

4555. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन किसानों के ऋण माफ करने पर विचार कर रही है, जिनकी 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जिन कृषकों की 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, उन कृषकों के ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की आम माफी अथवा उन्हें

बट्टे खाते डालने के हक में नहीं है, क्योंकि इसके कारण ग्रामीण ऋण प्रणाली को हानि होती है। तथापि, भारतयी रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1984 में बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि:—

(i) अल्पावधि के उत्पादन ऋणों का मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाए।

(ii) वर्तमान सावधि ऋण की किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना, और

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/निवेश, ऋणों आदि को उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक घरानों को स्वीकृत ऋण

4556. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या स्वीकृत राशि निर्धारित नियमों के अंतर्गत दी गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे औद्योगिक घरानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक उत्पादक उद्यमों को अपने साधारण बैंकिंग कारोबार के एक भाग के रूप में, उन की आवश्यकता पर आधारित ऋणों की जरूरतों का अनुमान लगाने के पश्चात् तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम स्वीकृत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक इकाइयों के आकार के अनुसार बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों की धनराशि के बारे में सूचना, उनकी डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून 1988, (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को स्वीकृत ऋण सीमा और बकाया ऋण निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ऋण सीमाएं	बकाया धनराशि
जून, 1988	2588	2016
जून, 1989	3088	2511

Cut in Staff and granting of extension in various Ministries

4557. SHRI KAMKAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Finance has issued instructions to various Ministries /Departments especially Industry Ministry to cut the staff strength to effect economy in expenditure;

(b) if so, the details thereof and whether the axe is to fall on lower staff;

(c) whether Government have reviewed the policy of granting extension/re-employment of Class-I Officers in various Ministries; and

(d) how many officers (Class-I) are on extension in various Ministries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) All the Ministries/Departments of the Government of India (including Ministry of Industry) have been asked to conduct a review and identify posts at different levels that could be considered for surrender/abolition.

(c) No, Sir.

(d) The information is not centrally maintained.

"म्यूचुअल फण्ड" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राप्त राशि

4558. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में "म्यूचुअल फण्ड स्कीम" के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि एकत्र की गई और इस तरह प्राप्त राशि के कितने प्रतिशत का उत्तर प्रदेश में निवेश किया गया; और